इकाई 12 भारत का सामाजिक एवं आर्थिक विकास : तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य*

संरचना

12.0 उद्देश्य

12.1 विषय प्रवेश

12.2 अंतर्राष्ट्रीय तुलना हेतु प्राधार

12.3 आर्थिक आयाम

12.3.1 प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद

12.3.2 संरचनात्मक आयाम

12.4 विकास में अभाव

12.4.1 निर्धनता

12.4.2 बेरोज़गारी

12.4.3 असमानता

12.5 विकास के सामाजिक आयाम

12.5.1 शैक्षिक स्थिति

12.5.2 स्वास्थ्य स्थिति

12.6 विकास के संश्लिष्ट सूचकांक

12.6.1 मानव विकास सूचकांक

12.6.2 सामाजिक प्रगति सूचकांक

12.6.3 विश्व सुख-सम्पन्नता सूचकांक

12.7 सारांश

12.8 सार-संक्षेप

12.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

12.10 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

12.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद, आप इस योग्य होंगे कि:

- अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक वर्णन हेतु एक आधार स्वरूप 'प्रति व्यक्ति आय' का प्रयोग करने की सीमाएँ समझ सकें;
- अपने सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु देशों की कोई तुलनात्मक रूपरेखा तैयार करने के लिए कोई प्राधार निर्दिष्ट कर सकें;
- वर्ष 1961–2018 के एक लंबे समय-प्राधार में अन्य देशों के साथ भारत के संवृद्धि वर्णन के 'आर्थिक आयाम' की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकें;

* प्रो. डी.एन. रेड्डी, उस्मानिया विश्वविद्यालय

- वर्ष 1961-2018 की अवधि में श्रीलंका और चीन की आर्थिक संवृद्धि के साथ भारत की आर्थिक संवृद्धि की तुलना में मुख्य अंतर उजागर कर सकें;
- अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक तुलनात्मक वर्णन में भारत में 'विकास की कमियों' का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर सकें;
- अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत में सामाजिक-क्षेत्र विकास की तुलना कर सकें; तथा
- 'विकास के विशद् सूचकांकों' पर टिप्पणी लिख सकें।

12.1 विषय प्रवेश

द्वितीय विश्व युद्ध के अंत और भारत समेत, अंधिकांश नव-स्वतंत्र देशों में उपनिवेशवाद की क्रमिक समाप्ति से ही 'विकास' को लोगों के लिए बेहतर जीवन-यापन दशाएँ उत्पन्न करने की दिशा में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। विकास को आरंभतः सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति जीडीपी के उच्चतर स्तर हासिल करने के रूप में समझा जाता था। इसके लिए, विकास हासिल करने के लक्ष्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि दरों के पदों में तय किए जाते थे। देशों के विकास-स्तर प्रति व्यक्ति आय-स्तर के पदों में मापे जाते थे। प्रति व्यक्ति आय में विकास मापने से इन बातों में मदद मिली– (i) देशों को विकसित और विकासशील के रूप में अलग-अलग मानना, तथा (ii) अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एवं विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा विकासशील देशों के लिए आवश्यक वित्तीय मदद को समर्थन दिया जाना।

जबकि देशों के विकास का मापन प्रति व्यक्ति आय के पदों में किया जाना जारी है, लोगों के जीवन यापन की दशा दर्शाने के लिए केवल प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर ही विचार किये जाने की उपयुक्तता पर सवाल उठाए गए हैं। यहाँ यह तर्क सही ही लगता है कि प्रति व्यक्ति आय एक औसत मात्र ही होती है और वह आय का वितरण नहीं दर्शाती। यह आलोचना उन देशों के मामलों में सुस्पष्ट दिखाई देती है जो उच्च प्रति व्यक्ति आय का लाभ तो पाते हैं परंतु क्षमताओं एवं स्वतंत्रता के लिहाज से विकास की मूलभूत उपलब्धियों का अभाव भी दर्शाते हैं। अतः, प्रति व्यक्ति आय बेहतर जीवन यापन के लिए एक साधन मात्र तो है मगर विकास के लिए पर्याप्त नहीं। विकास के लिए, इसे जनसंख्या विस्तार एवं लिंग-समानता स्तर के साथ रखकर ही देखा जाना चाहिए। इस तर्क ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण से विकास की अवधारणा को ही पलट दिया है। दूसरे शब्दों में, विकास मापदंड में सामाजिक-आर्थिक महत्त्व के अनेक आयामों पर विचार किया जाना चाहिए। संश्लिष्ट रूप से परिभाषित एवं संरचित इन मापदण्डों को ही फिर अंतर्देशीय तुलनाएँ करने के लिए आधार-स्वरूप लिया जाना चाहिए। इस इकाई के अगले ही भाग में, हम सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए अनेक देशों की तुलना हेतु एक व्यापक प्राधार पर चर्चा करेंगे। इस प्राधार के आधार पर ही आगे के भाग अन्य चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं के विकास का भारत के विकास से तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत करेंगे। अगले भाग में, उस आधार की रूपरेखा भी प्रस्तुत है जिस पर इन अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिदर्श चुना जाता है।

12.2 अंतर्राष्ट्रीय तुलना हेतु प्राधार

वे कारक, जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, इस प्रकार है – (i) आधारभूत आर्थिक आयाम, यथा जनसंख्या सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी में संवृद्धि, कुल रोज़गार एवं जीडीपी में कृषि का अंशदान, (ii) निर्धनता, भूख, असमानता एवं बेरोज़गारी के स्तरों की दृष्टि से आर्थिक विकास की कमियाँ; (iii) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं लिंग विकास स्थिति जैसे विकास संबंधी सामाजिक आयामों में प्रगति; तथा उपर्युक्त तीनों के आधार पर (iv) मानव विकास जैसे सामाजिक प्रगति का कोई एक अथवा अनेक विशद सूचकांक। इनमें से प्रत्येक में, भारत की स्थिति का अन्य चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति के साथ एक तुलनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करने हेतु, आगामी भागों में, हम इसी क्रम में, चर्चा आगे बढ़ाएँगे। तुलनार्थ देशों को चुनने के लिए, हम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप तक सीमित पाँच महाद्वीपों में से प्रत्येक से एक देश लेते हैं। विशेष रूप से, हम विकासशील और विकसित देशों में भेद के पचड़े में न पड़ते हुए, निम्नलिखित देशों को शामिल करते हैं– भारत, बांगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका (दक्षिण एशिया से); पूर्व एशिया से चीन; लैटिन अमेरिका से ब्राज़ील; दक्षिण अफ्रीका (अफ्रीका से); संयुक्त राज्य अमेरिका (उत्तरी अमेरिका से) तथा यूनाइटेड किंग्डम (यूरोप से)। हम यहाँ अपना तुलनात्मक वर्णन इन 10 देशों तक ही सीमित रखेंगे। ये 10 देश मिलकर विश्व जनसंख्या के आधे से अधिक (51 प्रतिशत) का लेखा-जोखा करते हैं। विशेषकर, चीन और भारत में ही मिलकर विश्व जनसंख्या का एक-तिहाई (36.6 प्रतिशत) अंश बसा है। अतः, इन दो देशों में जितना भी विकास होता हो वह वैश्विक मानव प्रगति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

अपने भेदपूर्ण ऋणदान उद्देश्यों से विश्व बैंक उक्त देशों को चार श्रेणियों में रखता है, यथा – (i) प्रति व्यक्ति $1025 (2018) से कम आय वाले निम्न आय देश, (ii) प्रति व्यक्ति $1026 – $3995 आय वाले निम्न मध्यम-आय देश, (iii) प्रति व्यक्ति $3996– $12375 आय वाले उच्च मध्यम आय देश, तथा (iv) प्रति व्यक्ति $12376 या उससे अधिक आय वाले उच्च आय। इस वर्गीकरण के अनुसार, हमारे प्रतिदर्श में लिए गए 10 देशों में से 4 दक्षिण-एशियाई देश, श्रीलंका को छोड़कर (जो कि एक उच्च मध्यम-आय देशकी पात्रता रखता है), निम्न मध्यम-आय समूह में ही आते हैं। श्रीलंका के साथ-साथ चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील भी उच्च मध्यम-आय समूह में रखे गए हैं। अमेरिका और इंग्लैंड सदा उच्च-आय समूह में ही रहे हैं। आप देखेंगे कि, कालांतर में, इन चार समूहों के भीतर देशों की स्थिति बदलती रहती है और इस कारण हमें 'विकास सूचक' विषयक विश्व बैंक के प्रकाशित आँकड़ों से स्वयं को अद्यतन रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए, श्रीलंका उच्च मध्यम-आय समूह में एक नव-प्रवेशक है जबकि नेपाल हाल ही में निम्न-आय से खिसककर निम्न मध्यम-आय समूह में चला गया है।

12.3 आर्थिक आयाम

वर्ष 1961–2011 की एक लंबी अवधि में, चीन को छोड़कर, शेष सभी एशियाई देश अपेक्षाकृत निम्न वृद्धि दर परिदृश्य में दुःख के दिन काटते नज़र आते हैं (जिन्हें जीडीपी में 4 प्रतिशत औसत वार्षिक संवृद्धि से नीचे दर्शाया जाता है) तालिका 12.1)।

इनकी संवृद्धि दरें नेपाल के 1.4 प्रतिशत की निचाई से श्रीलंका कर 3.3 प्रतिशत की ऊँचाई तक दिखाई पड़ती है।

तालिका 12.1 : विकास का आर्थिक आयाम

देश	जनसंख्या 2018 (दस लाख)	प्रतिव्यक्ति जीडीपी 2018 (वर्तमान US $)	जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर % 1961-2011	वृद्धि दर 2018	जीडीपी में कृषि का अंशदान (%) 2018	कुल रोज़गार में कृषि का अंशदान 2018 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भारत	1352	2010	3.1	6.8	14.6	43
बांगलादेश	161	1698	1.37	7.9	13.1	40
नेपाल	28	1033	1.4	6.7	25.3	70
पाकिस्तान	212	1482	2.6	5.8	22.9	41
श्रीलंका	21	4102	3.3	3.2	7.9	26
चीन	1392	9770	6.8	6.6	7.2	27
दक्षिण अफ्रीका	57	6374	—	0.8	2.2	5
ब्राज़ील	209	8920	—	1.1	4.4	9
अमेरिका	327	62795	—	2.9	0.9	1
इंग्लैंड	66	42944	—	1.4	0.6	1

स्रोत : 1) स्तंभ 4 (1961-2011 की वृद्धि दर) को छोड़कर, विश्व बैंक विकास संसूचक।
2) स्तंभ 4 के लिए : ड्रीस व सेन (2013)।

चीन एक अपवाद ही रहा, जहाँ 50 वर्ष की एक लंबी अवधि में 6.8 प्रतिशत की उच्चतम औसत वृद्धि दर दिखाई दी। परंतु हाल के वर्षों में, वर्ष 2018 में, श्रीलंका को छोड़कर, ये सभी देश उच्च-वृद्धि पथ पर पहुँच गए हैं (जिसे '5 प्रतिशत से ऊपर' के रूप में परिभाषित किया जाता है)। विशिष्ट रूप से, विकसित देशों को 0-2 प्रतिशत की शृंखला में अपनी निम्न वृद्धि दर के लिए उल्लेखनीय जाना जाता है। ऐसा इसलिए है कि विकसित देशों के पास बेहतर संस्थापित (यथा, औपचारिक) प्राधारिक आधार होता है। इससे एक ऐसी संतुलन प्राय स्थिति में रहकर उत्पादन एवं वितरण संबंधी अनेक कारकों को संबल मिलता है जहाँ इससे आगे वर्धमान पूँजी-उत्पादन अनुपात (ICOR) विकासशील देशों में इस अनुपात (ICOR) से अपेक्षाकृत कम ही रहेगा। इसके अलावा, विकसित देशों के पास अपनी जनसंख्या एवं श्रमशक्ति की अपेक्षा वृहत्तर जीडीपी मान होते हैं। ये सभी कारक विकासशील देशों के उदाहरण में उल्टे ही पाए जाते हैं, जहाँ प्रौद्योगिकीय अनुप्रेरण उच्चतर वर्धमान पूँजी-उत्पादन अनुपात (ICOR) लाभ देने वाला होता है।

12.3.1 प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद

प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के पदों में, चार दक्षिण-एशियाई देशों के बीच, भारत की स्थिति द्वितीय (वर्ष 2018 में $2010) है। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी ($4102) से लगभग दोगुनी है। परंतु चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी उच्चतम में शामिल है – यह श्रीलंका की प्रति व्यक्ति जीडीपी के दोगुने से भी अधिक ($9770) है। हमारे प्रतिदर्श में दो उच्च-आय देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी चीन से भी कई गुना अधिक है (इंग्लैंड की 4 गुना अधिक और अमेरिका की 6 गुना अधिक)। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के ये आँकड़े (PCI) चीन से तो कम मगर श्रीलंका से उच्च मान दर्शाते हैं (क्रमशः $6374 व $8920)।

12.3.2 संरचनात्मक आयाम

आय के उच्चतर स्तरों की ओर आरोहण में प्रमुख रूप से कृषिक अवस्था (जिसे कृषि में लगे 40 प्रतिशत से भी अधिक कार्यबल के रूप में परिभाषित किया जाता है, से प्रमुख रूप से विनिर्माणन् एवं सेवा क्षेत्र की अवस्था में विवर्तन शामिल होता है। इस मानदण्ड से, चार देशों, यथा– भारत, बांगलादेश, नेपाल और पाकिस्तार में कृषि में लगा कार्यबल 40 से 70 प्रतिशत के बीच है (बांगलादेश 40 प्रतिशत और नेपाल 70 प्रतिशत)। आय और रोज़गार के लिए कृषि पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भरता विकास का निम्न स्तर दर्शाती है। ऐसा इसलिए है कि कृषि पर कार्यबल के वृहत्तर भाग की निर्भरता (अपनी आय/जीडीपी में निम्न अंशदान के साथ) के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादकता (जिसे आय एवं कार्यबल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है) समस्त अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय (PCI) को निम्न रखती है। उक्त चारों देश अपना सकल घरेलू उत्पाद कृषि के उच्च अंशदान के साथ दर्शाते हैं (यथा 10-25 प्रतिशत की श्रृंखला में बांगलादेश में 13 प्रतिशत से लेकर नेपाल में 25 प्रतिशत तक)। कृषि से उद्योग की ओर प्राधारिक विवर्तन के साथ, विकसित देश न सिर्फ कृषि में अपने कार्यबल का निम्नतम अंश दर्शाने लगते हैं बल्कि उनकी जीडीपी में भी इस क्षेत्र का योगदान निम्नतम होता जाता है। इस लिहाज से अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ही उल्लेखनीय हैं, जहाँ कृषि पर निर्भर उनका कार्यबल मात्र 1 प्रतिशत है और जीडीपी में अंशदान 1 प्रतिशत से भी कम है।

अंततोगत्वा, वर्ष 1961-2018 की लंबी अवधि में श्रीलंका और चीन (वे दो पड़ोसी जिन्होंने प्रभावशाली ढंग से प्रगति की है – एक के भारत जितनी ही बड़ी जनसंख्या के साथ और दूसरे ने अपनी छोटी-सी जनसंख्या के साथ, वर्ष 2018 में केवल 2.1 करोड़) के साथ भारत के आर्थिक-वृद्धि विवरण में निम्नलिखित तीन प्रमुख अंतर उजागर करना अभीष्ट होगा–

- भारत और श्रीलंका दोनों ने 3 प्रतिशत औसत वार्षिक से किंचित् ऊपर लगभग बराबर जीडीपी संवृद्धि हासिल की है परंतु जनसंख्या आयाम में वृहद् अंतर के कारण, श्रीलंका की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी से दोगुनी है।

- लगभग 60 वर्ष की समयावधि में, हालाँकि चीन की संवृद्धि दर भारत की संवृद्धि दर से दोगुनी रही है। वर्ष 2018 में, दोनों देशों की संवृद्धि दर लगभग बराबर रही। भारत की 6.8 प्रतिशत और चीन की 6.6 प्रतिशत)। इससे यह तथ्य

उजागर होता है कि हाल के वर्षों में बेशक चीन की आर्थिक संवृद्धि में बड़ा उछाल आया, भारत भी उसके बराबर जा खड़ा हुआ है।

- चीन और श्रीलंका में कृषि का रोज़गार का अंश तुलनात्मक रूप से कम भी रहा और लगभग बराबर भी (वर्ष 2018 में क्रमशः 27 व 26 प्रतिशत)। कृषिगत रोज़गार में भारत में तुलनात्मक अंश आज भी काफ़ी ऊँचा है (वर्ष 2018 में 43 प्रतिशत)।

बोध प्रश्न 1 दिये गये स्थान मे अपना उत्तर लगभग 50.100 षब्दों में लिखें।

1) प्रतिव्यक्ति आय (PCI) को सीमाकारी क्यों माना जाता है, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय तुलना की दृष्टि से? फिर भी, इसे आज भी अंतर्राष्ट्रीय तुलना में कैसे प्रयोग किया जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) भारत के साथ अन्य अर्थव्यवस्थाओं का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत करने के लिए एक विश्लेषणात्मक प्राधार निर्दिष्ट करें।

.....

.....

.....

.....

.....

3) विकास के 'आर्थिक आयाम' के विश्लेषणार्थ कौन-से चरों पर विचार किया जाता है? अन्य देशों के साथ किसी तुलनात्मक वर्णन में इस लिहाज से भारत कहाँ खड़ा है?

.....

.....

.....

.....

.....

4) किस दृष्टि से भारत, श्रीलंका और चीन के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) अपनी विकास उपलब्धि के लिए बांग्लादेश और नेपाल क्यों उल्लेखनीय हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

6) 'विकास के प्राधारिक आयाम' से आप क्या समझते हैं? इस संबंध में श्रीलंका क्यों उल्लेखनीय है?

.....

.....

.....

.....

.....

12.4 विकास में अभाव

द्वितीय विश्व युद्धोपरांत अवधि में, अनेक विकासशील देशों ने नियोजित आर्थिक संवृद्धि की संकेंद्रित रणनीति शुरू की। इससे कुछ देशों में अपेक्षाकृत उच्चतर वृद्धि दरें देखने में आईं, परंतु भारत में 1990 के उत्तरार्ध तक भी ऐसा नहीं हुआ। 1970 के दशक तक यह समझा जाता था कि इनमें से अनेक देशों में संवृद्धि की उच्च दरों से अधिकांश लोगों की जीवन-दशा में कोई सुधार नहीं आया। दूसरे शब्दों में, अपेक्षाकृत उच्चतर संवृद्धि दरों के बावजूद, न सिर्फ गरीबी और बेरोज़गारी के उच्च स्तर बरकरार रहे, बल्कि आय असमानताएँ भी बढ़ी। ''संवृद्धि की सनक'' विषयक आलोचना बढ़ती जा रही थी, जहाँ जनसंख्या के निचले तबकों तक उसकी पहुँच संबंधी मुद्दे पर ध्यान दिए बिना ही जीडीपी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। इससे गरीबी, बेरोज़गारी और असमानता की दृष्टि से 'विकास में कमियों' पर ध्यान आकृष्ट हुआ। इस माँग के चलते, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और रोज़गार-सृजन नीतियों विषयक एक प्रत्यक्ष प्रयास पर एकाग्रता के साथ ध्यान दिया गया।

12.4.1 निर्धनता

निर्धनता अर्थात् गरीबी मापने के लिए, हर देश ने प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग और ईंधन, वस्त्र एवं परिवहन जैसी कुछ अनिवार्य वस्तुओं के उपभोग संबंधी मापदण्ड पर आधारित एक गरीबी-रेखा विकसित की हुई है। इसके अलावा, अंतर-देशीय तुलना हेतु कोई सामान्य आधार तलाशने के लिए, 'क्रय-शक्ति क्षमता (PPP) पर प्रति व्यक्ति उपभोग' संबंधी संकल्पना, विकसित हुई है। कीमतों में वृद्धि के कारण इस क्रय शक्ति तुल्यता (PPP) का मापदंड बदलता रहता है, जहाँ इसका वर्तमान स्तर $1.90 प्रतिदिन

पर निर्धारित है। यद्यपि कालांतर में निर्धनता स्तरों में गिरावट देखी गई है, आज भी, दक्षिण-एशियाई देशों (सिवाय श्रीलंका के) में लगभग एक-चौथाई जनसंख्या [20 प्रतिशत स्तर से ऊपर ही] अपना गरीबी अनुपात दर्शाती है (तालिका 12.2)। चूँकि बड़ी आबादियों की वजह से निर्धनता स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की बड़ी संख्या सामने आती है, भारत में कम से कम 28 करोड़ लोग (वर्ष 2011 में) निर्धनता स्तर से नीचे ही गुज़र-बसर करते थे।

तालिका 12.2 : आर्थिक विकास में अभाव

देश	गरीबी अनुपात (PPP $1.9 प्रतिदिन से नीचे %)	बेरोज़गारी दर (श्रम बल का प्रतिशत-2018)	असमानता (गिनी सूचकांक) 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
भारत	21.9 (2011)	6.5*	40.8
बांग्लादेश	24.8 (2016)	4.3	46.4
नेपाल	25.2 (2010)	1.2	32.8**
पाकिस्तान	24.3 (2015)	3.0	32.1
श्रीलंका	4.1 (2016)	4.3	48.9
चीन	3.1 (2017)	4.4	48.8
दक्षिण-अफ्रीका	55.5 (2014)	27.3	69.6
ब्राज़ील	उपलब्ध नहीं	12.2	52.5
अमेरिका	उपलब्ध नहीं	3.9	39.0
इंग्लैंड	उपलब्ध नहीं	3.8	32.0

*भारत की बेरोज़गारी– PLFS 2017-18, **विश्व बैंक डेटाबेस

स्रोत : 1) गरीबी दर एवं बेरोज़गारी के लिए : विश्व बैंक डेटाबेस।

2) असमानता के लिए : विश्व सुसमानता डेटाबेस (WID), विश्व आर्थिक विकास एवं अनुसंधान संस्थान (WIDER)।

ध्यान देने की बात है कि गरीबी का प्रतिव्यक्ति आय (PCI) से विलोम संबंध होता है, यथा– यह आय जितनी अधिक होगी उतना ही कम गरीबी का स्तर होगा। उदाहरण के लिए, PCI $9770 के साथ चीन 3.1 प्रतिशत का निम्नतम गरीबी अनुपात दर्शाता है, श्रीलंका $4102 PCI के साथ 4.1 प्रतिशत का निम्नतम गरीबी अनुपात दर्शाने वाला दूसरा देश है। विशिष्ट रूप से, 1000-2000 डॉलर की श्रृंखला में अपनी यह आय (PCI) दर्शाने वाले भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अपनी आबादी का एक बट्टे पाँच भाग (20 प्रतिशत) निम्न गरीबी स्तर पर ही देखते हैं। दक्षिण-अफ्रीका एक अत्यांतिक उदाहरण है, जहाँ बेशक उसकी यह आय (PCI) $6374 से ऊँची है, उसका गरीबी अनुपात भी 56 प्रतिशत की ऊँचाई छूता है (वर्ष 2014 में)।

12.4.2 बेरोज़गारी

सभी देशों में व्याप्त बेरोज़गारी की व्याख्या ध्यानपूर्वक किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा विकासशील देशों में अनौपचारिक क्षेत्र की बहुत अधिक विद्यमानता के कारण है

क्योंकि निर्धन वर्ग बेरोज़गार रहना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। गरीब आदमी कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है– दिहाड़ी या पगार और काम के घंटे या दिन जो चाहे भी हों। तद्नुसार, वे बेरोज़गार नहीं कहे जा सकते, बेशक वे बहुत कम पारिश्रमिक पर प्रायः अल्प-रोज़गार प्राप्त होते हैं। अतएव, भारत जैसे अपेक्षाकृत अल्पविकसित देशों में, जहाँ लगभग 90 प्रतिशत रोज़गार अनौपचारिक है, बेरोज़गारी को प्रायः बहुत निम्न दर्शाया जाता है (वर्ष 2018 में 6.5 प्रतिशत, तालिका 12.2)। दक्षिण-अफ्रीका (27 प्रतिशत) और ब्राज़ील (12 प्रतिशत) में बेरोज़गारी की ऊँची दरें औपचारिक रोज़गार के ऊँचे अनुपात के कारण हैं, जहाँ अल्प-रोज़गार की गुंजाइश कम ही होती है, यथा– या तो आपको औपचारिक रोज़गार मिलता है अथवा आप बेरोज़गार रहते हैं। इसके विपरीत, सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों के अभाव के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोज़गारी का बड़ा अनुपात और खुली बेरोज़गारी का ऊँचा अनुपात दोनों ही देखने में आते हैं।

12.4.3 असमानता

यद्यपि भारत समेत अनेक विकासशील देशों ने अपनी विकास रणनीति वितरण स्तर पर न्यायशील संवृद्धि पर ज़ोर देते हुए शुरू की, वर्ष-दर-वर्ष असमानता में इज़ाफा ही होता रहा है। यह विडंबनापूर्ण सत्य ही है कि जब इन देशों में संवृद्धि मंथर गति से हो रही थी, यहाँ असमानता बहुत कम थी। परंतु जब वे उच्च संवृद्धि प्रक्षेप-पथ पर नज़र आने लगे, असमानता भी बढ़ने लगी। असमानता की यह उच्च कोटि अशांतिकर मानी जाती है, इतनी अशांति कर कि अब इसे प्रमुख विकास चुनौती के रूप में देखा जाने लगा है। परंपरागत रूप से, आय वितरण में असमानता गिनी अनुपात के रूप में व्यक्त की जाती है (यथा, गिनी गुणांक को 100 से गुणा कर प्राप्त प्रतिशत के रूप में)। परंतु चूँकि विकासशील देशों में स्वयं आय विषयक आँकड़े ही प्राप्त करना कठिन होता है (पुनः, अनौपचारिक रोज़गार की बड़े पैमाने पर विद्यमानता के कारण), आय का आकलन परिवार उपभोग सर्वेक्षणों के आधार पर परोक्ष रूप से किया जाता है। उपभोग आँकड़ों पर आधारित असमानता अनुमान असमानता का अल्पाकलन ही दर्शाते हैं। बहरहाल, हाल ही में, विश्व असमानता डेटाबेस (WID) की पहल के कारण, सभी देशों के आय विषयक आँकड़े कुछ अनूठी विधियों के आधार पर तैयार किए जा रहे है, जो कि देशों के बीच आँकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए अपनाई जाती हैं। उक्त डेटाबेस (WID) द्वारा प्रस्तुत असमानता विषयक आँकड़े (तालिका 12.2 दर्शाते हैं कि दक्षिण-एशियाई विकासशील देशों के बीच, असमानता पाकिस्तान में 32 प्रतिशत से लेकर चीन व श्रीलंका दोनों में 49 प्रतिशत तक व्याप्त है। इसके अलावा, आय बढ़ने के साथ ही, विकासशील देशों में असमानता तेज़ी से बढ़ती दिखाई देती है। यह दक्षिण-अफ्रीका के मामले में भी सत्य है, जहाँ उच्चतम गिनी सूचकांक 70 प्रतिशत नज़र आता है (कुछ मध्य-पूर्वी देशों के बाद विश्व में उच्चतम में एक)। एक अन्य उदाहरण श्रीलंका है जो अधिकांश विकास सूचकों में काफी बेहतर स्थित रखने के बावजूद, दक्षिण एशिया में 49 प्रतिशत (चीन के बराबर) का उच्चतम असमानता सूचकांक दर्शाता है। विकसित देशों के पक्ष में, यह अंक इंग्लैंड में 32 प्रतिशत और अमेरिका में 39 प्रतिशत के बीच है, जो कि नेपाल, पाकिस्तान और भारत की दक्षिण-एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से तुलनीय स्तर पर हैं।

बोध प्रश्न 2 दिये गये स्थान मे अपना उत्तर लगभग 50.100 षब्दों में लिखें।

1) 'विकास में अभावों' से आप क्या समझते हैं?

2) क्या यह सत्य है कि प्रतिव्यक्ति आय (PCI) में वृद्धि के साथ गरीबी घटने लगती है? क्या इस विलोम संबंध का कोई अपवाद है? उदाहरण दें।

3) बेरोज़गारी का मापन क्यों विकासशील देशों में एक समस्या बन जाता है?

4) विभिन्न देशों के बीच तुल्य आय के आँकड़े तैयार करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? इस प्रकार के आँकड़े तमाम देशों में असमानता के विषय में क्या दर्शाते हैं?

5) विकसित देशों में असमानता का विस्तार कितना है? यह विकासशील देशों में असमानता से किस प्रकार तुलनीय है?

12.5 विकास के सामाजिक आयाम

जब से विकास के मापदंड स्वरूप प्रति व्यक्ति आय की सीमाबद्धताओं के विषय में सवाल उठाए जाने लगे हैं, विकास के क्षेत्राधिकार को विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। विकास में कमियों, जैसे गरीबी और बेरोज़गारी का लगातार बने रहना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक आयामों की उपेक्षा कर जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी की वृद्धि पर ही एकाग्र रहना परिणाम माना जाता है। पिछले दो दशकों में, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आयामों पर उत्तरोत्तर ध्यान दिया गया है। ऐसा मुख्य रूप से इस बोध की वजह से है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार लोगों की क्षमताएँ बढ़ाने में अतीव महत्त्व रखता है। उत्कृष्ट क्षमताएँ, बदले में, लोगों का उत्पादनकारी निष्पादन बढ़ाने में और विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का बेहतर सदुपयोग करने में मदद करती हैं। इस भाग में, हम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के सूचकों के अनुसार देशों की स्थिति पर विचार करेंगे।

12.5.1 शैक्षिक स्थिति

परंपरागत रूप से, 'वयस्क साक्षरता दर' को शैक्षिक स्थिति के एक सूचक स्वरूप लिया जाता है। इससे अपेक्षा थी कि यह लोगों की शैक्षिक स्थिति में इतिहासपरक उपेक्षा अथवा उपलब्धि को उजागर करेगी। परंतु वर्तमान में, शैक्षिक उपलब्धियाँ शिक्षा की 'सुलभता, निष्पक्षता एवं गुणवत्ता' के पदों में बताई जाती हैं। इस प्रवृत्ति के चलते, यहाँ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेगा– 'शिक्षा की विभिन्न स्तरों पर सुलभता'। गुणवत्ता के विषय में, विश्व बैंक द्वारा परिभाषित 'शिक्षा प्राप्ति निर्धनता' सूचक पर विचार किया जाता है। 'ज्ञान-शून्यता' या ज्ञान के अभाव को विश्व बैंक द्वारा इन शब्दों में परिभाषित किया गया है– '10 वर्ष की आयु तक किसी लघु, आयु-अनुकूल मूलपाठ को पढ़ने व समझने में असमर्थ होना।' इस सूचक के केंद्र में आरंभिक बाल्यकाल एवं स्कूली शिक्षा है।

वयस्क साक्षरता अनुपात किसी भी देश की शैक्षिक स्थिति का एक व्यापक सूचकांक प्रदान करता है। इसका अपेक्षाकृत निम्न स्तर शिक्षा के प्रति अपर्याप्त अवधान को इंगित करते हैं। भारत में वयस्क साक्षरता दर (74%) पाकिस्तान (59%) व नेपाल (68%) से बेहतर है परंतु अन्य देश [श्रीलंका (92%), दक्षिण-अफ्रीका (87%), ब्राज़ील (93%) और चीन (97%)] इस लिहाज से भारत से काफी आगे हैं (तालिका 12.3)। 'स्कूली शिक्षा' की सुलभता' के लिहाज से, अधिकांश देशों में प्राथमिक शिक्षा की सुलभता चूँकि लगभग 100 प्रतिशत है, यहाँ माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन दर (GER) पर विचार किया जाता है। इस संबंध में, दक्षिणा एशिया के देशों में, अब भी श्रीलंका को छोड़कर, अन्य चार देशों के उपयुक्त आयु-वर्ग के एक-चौथाई से कुछ अधिक बच्चे 'स्कूल छोड़ चुके' हैं। पाकिस्तान, जिसकी माध्यमिक शिक्षा में नामांकन दर 43 प्रतिशत है, इन क्षेत्र में अन्य देशों से पीछे ही हैं।

तालिका 12.3 : एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विकास की स्थिति (2018-2019)

देश	वयस्क साक्षरता दर (%)	माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन	तृतीयक शिक्षा में सकल नामांकन	स्कूल के माध्य वर्ष (25+ जनसंख्या के लिए)	निम्न माध्यमिक शिक्षा संपन्न जनसंख्या %	शिक्षा पर राजकीय व्यय (जीडीपी की तुलना में %)	स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता (ज्ञान-शून्यता)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भारत	74	73	28	6.5	37.6	3.8	54.8
बांग्लादेश	74	73	21	6.4	43.6	2.0	57.2
नेपाल	68	74	12	3.5	26.9	5.2	उपलब्ध नहीं
पाकिस्तान	59	43	9	5.0	36.4	2.9	74.5
श्रीलंका	92	98	20	10.9	81.6	2.8	14.4
चीन	97	88	51	10.6	65.3	1.9	18.2
दक्षिण-अफ्रीका	87	105	22	10.2	72.3	6.2	79.8
ब्राज़ील	93	101	51	8.0	60.0	6.2	48.4
अमेरिका	—	99	88	13.8	96.0	5.0	7.9
इंग्लैंड	—	126	60	13.2	99.7	5.5	3.4

स्रोत : विश्व विकास संसूचकों पर विश्व बैंक डेटाबेस

यह निरंतर चिंता का विषय बना हुआ है कि उच्चतर कौशल क्षमताओं के प्रति भावी नौकरियों के वर्धमान पूर्वाग्रह के साथ, रोज़गार में प्रवेशार्थ शिक्षा की न्यूनतम वांछनीयता 'माध्यमिक-शिक्षा संपन्न' हो जाएगी। इस संबंध में, माध्यमिक शिक्षा में 98 प्रतिशत नामांकन के साथ श्रीलंका दक्षिण-एशिय में सर्वश्रेष्ठ विजेता के रूप में खड़ा है। बहरहाल, स्कूली शिक्षा के दो आयाम हैं– एक है नामांकन और दूसरा है 'विभिन्न स्तरों पर स्कूली शिक्षा की संपूर्ति'। इस दृष्टिकोण से, 25 वर्ष या उसके अधिक आयु-वर्ग में जनसंख्या के लिए 'स्कूली शिक्षा के माध्य वर्ष' नेपाल में निम्नतम (3.5 वर्ष) हैं। इसके बाद आते हैं– पाकिस्तान (5 वर्ष), बांग्लादेश (6.4 वर्ष), भारत (6.5 वर्ष), ब्राज़ील (8 वर्ष), चीन (10.6 वर्ष) और श्रीलंका (10.9 वर्ष)। विकसित देशों में, यह माध्यम आज भी ऊँचा है– इंग्लैंड 13.2 वर्ष; अमेरिका 13.8 वर्ष। जब हम तृतीयक शिक्षा में सकल नामांकन दर (GER) पर विचार करते हैं तो भारत (28%) के अंक श्रीलंका (20%) समेत अन्य दक्षिण-एशियाई देशों से बेहतर ही मिलते हैं। परंतु वह चीन और ब्राज़ील (दोनों 51%) से काफी पीछे है। यह प्रतिशतता इंग्लैंड (60%) और अमेरिका (88%) के मामले में और अधिक है। यह दृष्टिकोण व्यापक रूप से साझा किया जाता है कि अधिकांश विकासशील देशों में शिक्षा पर राजकीय व्यय न्यूनतम वांछित (जीडीपी का

6%) से काफी कम होता है। बड़ी दिलचस्प बात है कि ऐसा वस्तुतः अधिकांश दक्षिण-एशिया और चीन (1.9%) में ही नहीं बल्कि अमेरिका (5%) और इंग्लैंड (5.5%) में भी है। ऐसा शायद इसलिए है कि उच्च-आय देशों में काफी उच्चतर शिक्षा निजीकृत हो चुकी है। इसके अलावा, अमेरिका और चीन जैसे देशों की जीडीपी चूँकि भारत के मुकाबले कई लाख करोड़ डॉलर अधिक है, इन देशों की छोटी-सी प्रतिशतता भी अचर पदों में ऊँची ही होती है।

शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में, हम 'ज्ञान-शून्यता' के अनुमान प्रयोग करते हैं। चूँकि यह सूचकांक पठन-पाठन कौशल पर ज़ोर देता है, एक प्रकार से यह अनेक विषयों में बुनियादी शिक्षा को केंद्र में रखता है। इसे 'स्कूल छोड़ चुके बच्चों' और 'स्कूल में ऐसे बच्चों का अनुपात जिन्हें न्यूनतम-प्रवीणता हासिल नहीं हुई है' के संयोजन के रूप में मापा जाता है। अतएव, यह 'स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता' का मापदंड होता है। भारत और बांग्लादेश के ज्ञान-शून्यता' अनुपात क्रमशः 55 और 57 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि इन दोनों देशों में लगभग दो-तिहाई बच्चे प्रत्याशित प्राप्त ज्ञान-कौशल दर्शाने में असफल रहते हैं। अन्य देशों की सदृश प्रतिशतताएँ इस प्रकार हैं– चीन (18%), श्रीलंका (14%), अमेरिका (8%) और इंग्लैंड (3%)। इसका अर्थ है कि सापेक्षिक पदों में, इन देशों में शिक्षा की गुणवत्ता अभिहित रूप से ऊँची है।

12.5.2 स्वास्थ्य स्थिति

जनस्वास्थ्य की दशा विकास का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है जो केवल प्रतिव्यक्ति आय को केंद्र में रखकर शायद स्थिति को स्पष्ट रूप से न दर्शा पाए। इसी प्रकार, महज जीवन-प्रत्याशा के उच्च वर्ष भी स्वास्थ्य के अन्य पहलुओं को संभवतः उजागर न करते हों। उदाहरण के लिए, लगभग सभी देशों में स्त्री जीवन-प्रत्याशा पुरुष जीवन-प्रत्याशा से अधिक है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि महिलाओं की स्वास्थ्य दशा पुरुषों से बेहतर है। इसीलिए, स्वास्थ्य की एक सूचक शृंखला पर विचार किया जाना आवश्यक है (तालिका 12.4)। भारत में जीवन-प्रत्याशा (69), बांग्लादेश (72) और नेपाल (70) से कम है। ये दोनों देश 'शिशु मर्त्यता दर' (IMR) के जिहाल से भी बेहतर स्थिति दर्शाते हैं [बांग्लादेश (25), नेपाल (27), भारत (30)]। श्रीलंका की यह दर (IMR) निम्नतम (6) है और यह चीन (7), अमेरिका (6) और इंग्लैंड (4) के तुल्य है। मातृ मर्त्यता दर (MMR) श्रीलंका (36) को छोड़कर सभी दक्षिण-एशियाई देशों में बहुत ऊँची (>140) है। एक कहीं अधिक विक्षुब्ध करने वाला अभिलक्षण है – कुपोषण की उच्च दर जो पाँच वर्ष से नीचे के बच्चों में एक प्रकार का 'रुद्ध विकास और अपक्षय' दर्शाती है। रुद्ध विकास की दर भारत, बांग्लादेश और नेपाल में ऊँची है (इन सभी 3 देशों में >35) और पाकिस्तान में यह और भी संकटरपूर्ण (45) है। रुद्ध विकास के उच्च स्तर आरंभिक बाल्यकाल में निकृष्ट स्वास्थ्य को ही दर्शाते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उनके वयस्क होने पर प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। स्वास्थ्य सूचकों पर चीन का कार्य-प्रदर्शन इसीलिए अमेरिका व इंग्लैंड जैसे विकसित देशों के तुल्य है।

किसी देश की स्वास्थ्य स्थिति के दो प्रमुख निर्धारक तत्व हैं – (i) कुल स्वास्थ्य व्यय में राजकीय व्यय का प्रतिशत, और (ii) जीडीपी की प्रतिशत स्वरूप व्यक्त स्वास्थ्य पर राजकीय व्यय। दक्षिण-एशिया में चार निकृष्ट प्रदर्शन करने वाले देश (यथा– भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान) ऐसे देशों में भी गिने जाते हैं जहाँ स्वास्थ्य पर राजकीय व्यय अल्पतम (<30%) है। इसका अर्थ है कि इन देशों में लगभग तीन-

चौथाई स्वास्थ्य व्यय 'जेब से खर्च', यथा निजी व्यय, से ही पूरा होता है। इन देशों में जीडीपी के अनुपात स्वरूप भी स्वास्थ्य पर राजकीय व्यय कम है (बांग्लादेश में जीडीपी के 0.4% से लेकर नेपाल में 1.2% तक)। इस संबंध में सरकार की संलिप्ति अन्य देशों में कहीं अधिक है [श्रीलंका (1.7%), चीन (2.9%), ब्राज़ील (3.9%), दक्षिण अफ्रीका (4.4%)]। अमेरिका एवं इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में, स्वास्थ्य में सरकार की अंतर्भावितता और भी अधिक है (इंग्लैंड 7.8%; अमेरिका 14%)। तद्नुसार, यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य पर राजकीय वयय में संतोषजनक वृद्धि किए बिना, भारत उच्च संवृद्धि दरों एवं वर्धमान प्रतिव्यक्ति आय के बावजूद विकास के सामाजिक आवाम विषयक अपना संवर्ग सुधारने की स्थिति नहीं आ पाएगा।

तालिका 12.4 : तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य विकास (2017-2018)

देश	जन्म के समय जीवन-प्रत्याशा	शिशु-मर्त्यता दर (प्रति 1000 अमृत जन्म)	मातृ मर्त्यता दर (प्रति 1,00,000 अमृत प्रसव)	5 वर्ष से नीचे के बच्चों में रुद्ध विकास (%)	अपक्षय रोग (कदानुसार वज़न) (5 वर्ष से कम बच्चों का %)	कुल स्वास्थ्य व्यय के %स्वरूप राजकीय व्यय	राजकीय व्यय (जीडीपी का %) स्वास्थ्य पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भारत	69	30	145	38.4	21	25.4	0.9
बांग्लादेश	72	25	173	36.6	14.3	18.0	0.4
नेपाल	70	27	186	35.8	9.7	18.6	1.2
पाकिस्तान	67	57	140	45.0	10.5	27.9	0.8
श्रीलंका	77	6	36	17.3	15.1	43.1	1.7
चीन	76	7	29	8.1	1.9	58.0	2.9
दक्षिण-अफ्रीका	64	29	119	27.4	2.5	53.7	4.4
ब्राज़ील	75	13	60	7.1	1.6	33.2	3.9
अमेरिका	79	6	19	2.1	0.5	81.9	14.0
इंग्लैंड	81	4	7	.	.	80.2	7.8

स्रोत : विश्व विकास संसूचक विषयक विश्व बैंक डेटाबेस

12.6 विकास के संश्लिष्ट सूचकांक

भाग 12.3 व 12.5 में हमारी चर्चा के विषय रहे विकास के सामाजिक एवं आर्थिक आयाम संबंधी वैयक्तिक सूचक हमें प्रतिवयक्ति आय जैसे किसी एकल मापदंड द्वारा मिले-जुले विकास को समझने में मदद नहीं करते। इसीलिए, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक घटकों को किसी एकल मान अथवा सूचकांक में संयोजित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि किसी अपेक्षाकृत अधिक बोधगम्य मापदंड पर पहुँचा जा सके। इनमें से कुछ मापदंड हैं – (i) मानव विकास सूचकांक (HDI), (ii) सामाजिक प्रगति सूचकांक, और (iii) विश्व सुख-सम्पन्नता सूचकांक।

12.6.1 मानव विकास सूचकांक

विकास के किसी बोधगम्य मापदंड के लिए आरंभिक प्रयास वर्ष 1990 में 'मानव विकास सूचकांक' (HDI) के रूप में किया गया। विकास का उद्देश्य लोगों के लिए दीर्घ, स्वस्थ एवं रचनात्मक जीवन भोगने में सक्षम बनाने वाला परिवेश सृजित करना होता है, इस सूचकांक (HDI) ने विकास को 'लोगों के विकल्प विस्तृत करने की प्रक्रिया' के रूप में परिभाषित किया। ये विकल्प तीन अनिवार्य पहलुओं में देखें जा सकते हैं, यथा– (i) एक दीर्घ एवं स्वस्थ्य जीवन व्यतीत करना, (ii) ज्ञान अर्जित करना, और (iii) एक शालीन जीवन-स्तर हेतु आवश्यक संसाधनों की सुलभता। इन तीन पहलुओं के अनुरूप, यह सूचकांक (HDI) तैयार करने के लिए तीन पृथक् घटक चुने जाते हैं। ये घटक हैं – (i) 'जन्म के समय जीवन-प्रत्याशा' में मापित दीर्घायुता, (ii) साक्षरता से मापा जाने वाला ज्ञान, तथा (iii) प्रति व्यक्ति आय द्वारा निरूपित एक शालीन जीवन बिताने हेतु संसाधन। वर्ष 1990 से, कुछ फेर-बदल के साथ, इस सूचकांक (HDI) को अधिकांश देशों में आकलित किया जा रहा है। तालिका 12.5 वर्ष 2019 के लिए HDI मान एवं संवर्ग दर्शाती है।

तालिका 12.5 : विकास के विशद सूचकांक

देश	मानव विकास सूचकांक 2019		सामाजिक प्रगति सूचकांक 2018		विश्व सुख-संपन्नता सूचकांक 2016-18
	मान	संवर्ग अंक	समंक	संवर्ग अंक	संवर्ग अंक
भारत	0.65	129	56.3	100	140
बांग्लादेश	0.61	135	52.2	108	125
नेपाल	0.58	147	56.1	101	100
पाकिस्तान	0.56	152	49.2	115	67
श्रीलंका	0.78	71	68.0	67	130
चीन	0.76	85	64.6	87	93
दक्षिण-अफ्रीका	0.71	113	–	–	106
ब्राज़ील	0.76	79	72.7	49	32
अमेरिका	0.92	15	–	–	19
इंग्लैंड	0.92	15	88.7	13	15

अपने संवर्ग अंक 129 के साथ (कुल 189 देशों में), भारत, बांग्लादेश (135), नेपाल (147) और पाकिस्तान (152) से किंचित् बेहतर स्थिति दर्शाता है। यह चीन (85) और श्रीलंका (71) की तुलना में काफी नीची है। बड़ी ही रोचक बात है कि उक्त सूचकांक (HDI) संवर्ग निर्धारण आय निष्पादन के अनुरूप होता है, विशेषकर पाँच दक्षिण-एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में से तीन के लिए [देखें तालिका 12.1 (कोष्ठक में PCI) : श्रीलंका ($4102), भारत ($2010) और बांग्लादेश ($1698)]। पाकिस्तान की प्रतिव्यक्ति आय नेपाल से अधिक है परंतु HDI संवर्ग के लिहाज से, नेपाल कर संवर्ग (147) पाकिस्तान (152) से बेहतर है।

12.6.2 सामाजिक प्रगति सूचकांक

समाजिक प्रगति सूचकांक (SPI) 'सामाजिक प्रगति नियोग' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय असैनिक समाज संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सामाजिक प्रगति को इन शब्दों में परिभाषित करता है – 'अपने नागरिकों की मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की किसी समाज की क्षमता।' यह ऐसे निर्माण खंड स्थापित कर इसकी उपलब्धि को निर्दिष्ट करता है जो नागरिकों एवं समुदायों को अपने जीवन की गुणवत्ता सुधारने व कामय रखने में मदद करते हैं। तद्नुसार, इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी देश में अपने पूर्ण सामर्थ्य तक पहुँचने हेतु सभी लोगों के लिए आवश्यक दशाएँ उत्पन्न हों। यह सूचकांक (SPI) 54 संकेतकों पर आधारित है। इनके दायरे में तीन बुनियादी पहलू आते हैं, यथा– मूलभूत मानवीय आवश्यकताएँ, स्वस्थ रहने के आधार, तथा अवसर। यह सूचकांक वर्ष 2014 से नियमित प्रकाशित हो रहा है। हमारे प्रतिदर्श में वर्ष 2018 का यह सूचकांक देशों के संवर्ग अंक इस प्रकार दर्शाता है– भारत (100), बांग्लादेश (108), नेपाल (101) और पाकिस्तान (115)। ये चार देश संवर्गित 146 देशों के लगभग तल पर स्थित हैं। इस लिहाज से चीन (87), श्रीलंका (67), ब्राज़ील (49) और इंग्लैंड (13) काफी ऊपर हैं।

12.6.3 विश्व सुख-सम्पन्नता सूचकांक

विगत जुलाई 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। इसमें सदस्य देशों को अपने नागरिकों की सुख सम्पन्नता मापने और उसे अपनी शासकीय नीतियों के दिशा-निर्देश हेतु प्रयोग करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके अनुपालन में, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) ने 'आत्मनिष्ठ स्वास्थ्य' के मापन हेतु दिशा-निर्देश' प्रस्तुत किए। प्रथम 'विश्व सुख-सम्पन्नता रिपोर्ट' वर्ष 2012 में प्रकाशित हुई। छह संकेतकों (भ्रष्टाचार, उदारता, जीवन-वर्ष, जीवनानुभव, स्वतंत्रता का भाव और प्रति व्यक्ति जीडीपी) के आधार पर, विश्व सुख-सम्पन्नता सूचक (WHI) एक 0 से 10 के पैमाने पर तैयार किया जाता है। वर्ष 2016-2018 की रिपोर्ट में 156 देशों का सर्वेक्षण कर उन्हें संवर्गबद्ध किया गया (तालिका 12.5)। अपनी संवर्ग अंक 140 के साथ भारत यहाँ इस तुल्य देशों के तल में नज़र आता है। ऊपर विचाराधीन अधिकांश अन्य सामाजिक-आर्थिक आयामों में एक काफी नीचे नज़र आने वाले कार्य-निष्पादक के रूप में पाकिस्तान सुख-सम्पन्नता के लिहाज से सभी छह एशियाई देशों में शीर्ष पर दृष्टिगत होता है (67)। श्रीलंका जो अनेक पहलुओं से एशिया में शीर्ष पर नज़र आया, सुख-संपन्नता में काफी नीचे (130) दिखाई पड़ता है। इस संबंध में, ब्राज़ील (32), अमेरिका (19) और इंग्लैंड (15) अपनी-अपनी श्रेणियों में अग्रणी नज़र आते हैं। 'स्वास्थ्य' का विषय, बहरहाल, आज भी एक नई (nascent) अवधारणा ही है। कालांतर में और अधिक सुधार के साथ, इस असंगति को दूर करने में निश्चय ही सफलता मिलेगी।

बोध प्रश्न 3 दिए गए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50–100 षब्दों में लिखें।)

1) किसी देश में शिक्षा का स्तर मापने के लिए ऐतिहासिक रूप से 'वयस्क साक्षरता' को विचाराधीन क्यों रखा गया? हाल ही में पुनरानुस्थापित अवधारणा क्या रही है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन दर (GER) के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) 'स्कूली शिक्षा के मध्य वर्ष' विषयक भारत की स्थिति क्या है? किस लिहाज से, भारत की स्थिति दक्षिण एशिया क्षेत्र के अन्य देशों से बेहतर है?

.....

.....

.....

.....

.....

4) किसी देश की स्वास्थ्य प्रस्थिति के दो प्रमुख निर्धारक तत्व बताएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

5) 'सामाजिक प्रगति' को परिभाषित करें। सामाजिक प्रगति सूचकांक के संदर्भ में भारत की सापेक्ष स्थिति क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

12.7 सार-संक्षेप

विभिन्न देशों के सापेक्ष विकास को मापने हेतु एक साधन स्वरूप प्रति व्यक्ति आय (PCI) की सीमाबद्धताओं के चलते 'मानव विकास सूचकांक' और 'सामाजिक प्रगति सूचकांक' जैसे संश्लिष्ट सूचक तैयार करने पड़े। इन मापदंडों के विकास ने उन

बुनियादी कारकों को यथायोग्य महत्त्व दिया जाना संभव बना दिया जो किसी देश में सम्पत्ति सृजन में अहम् होते हैं। इस प्रयास में, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक कारकों को यथोचित अधिप्रतिनिधित्व मिला है। इस इकाई में किए गए 10 देशों के तुलनात्मक वर्णन में, भारत की स्थिति को तीन एशियाई पड़ोसियों– नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान – से किंचित् ही ऊपर देखा गया। भारत के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों सामाजिक क्षेत्रों में राजकीय व्यय में संतोषजनक वृद्धि अनिवार्यतः आवश्यक है ताकि वह अपने समग्र विकास में वर्तमान श्रेणी बढ़ाकर अपनी स्थिति सुधार सके।

12.8 शब्दावली

ज्ञान-शून्यता : दस वर्ष की आयु तक किसी लघु आयु-अनुकूल मूलपाठ को पढ़ने व समझने में असमर्थता। यह शिक्षा की गुणवत्ता आँकने हेतु विश्व बैंक द्वारा विकसित एक संसूचक है।

सामाजिक प्रगति सूचकांक : अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में किसी समाज की क्षमता आँकने हेतु विकसित एक मापदंड। इसके दायरे में मानवीय आवश्यकताओं के अलावा दो अन्य पहलू भी आते हैं, यथा – स्वास्थ्य के मूल आधार एवं अवसर।

12.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

Dreze, Jean and Amartya Sen (2013). An Uncertain Glory: India and Its Contradictions, Allen Lane, Penguin Books, London.

Nayyar, Deepak (2019). Resurgent Asia: Diversity in Development, Oxford University Press, New Delhi.

12.10 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) प्रतिव्यक्ति आय (PCI) आय के वितरण से कोई ताल्लुक न रख सिर्फ प्रतिव्यक्ति आय के कुल विस्तार से ही संबंध रखती है। यह विभिन्न देशों को विकसित-विकासशील के रूप में भिन्न-भिन्न दर्शाने और अर्थव्यवस्थाओं को उनके औसत आय-स्तर के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है।

2) यह प्राधार विकासशील-विकसित भेद से परे सभी श्रेणियों के देशों का प्रतिनिधित्व करता हो। इसमें विश्व जनसंख्या का यथेष्ट रूप से बड़ा भाग शामिल किया गया हो। चुने गए देशों का नमूना न्यायोचित हो क्योंकि इसमें विश्व जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक भाग आ जाता है।

3) जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति जीडीपी, जीडीपी में दीर्घावधि औसत वार्षिक वृद्धि दर, कुल रोज़गार में कृषि का अंश तथा जीडीपी में उसका योगदान।

4) वर्ष 1961-2011 के दौरान 6.8 प्रतिशत की एक प्रभावशाली दीर्घावधि वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज़ कराके चीन ने भारत के मुकाबले एक ऊँची छलाँग लगाई। इस संबंध में भारत यद्यपि कम ही प्रभाव छोड़ने में सफल रहा, उसने हाल के वर्षों में चीन के समकक्ष आ जाने का पराक्रम कर दिखाया है। निम्नतर कृषि रोज़गार एवं कृषि जीडीपी अंश (7.9 प्रतिशत) के पदों में अपने प्राधारिक परिवर्तन

के लिए श्रीलंका का खिसककर उच्चतर मध्यम-आय वर्ग में चले जाना गौरतलब है।

5) बांग्लादेश का 'उच्चतर मध्यम-आय समूह' की ओर खिसक जाना और नेपाल का 'निम्न आय' से खिसरकर 'निम्नतर मध्यम-आय समूह' में चले जाना।

6) प्राधारिक आयाम का अर्थ है – अपने कृषि क्षेत्र से किसी देश का रोज़गार एवं जीडीपी अंश घटाकर प्रभावशाली परिवर्तन। पाँच दक्षिण-एशियाई देशों के उदाहरण में श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश है जो चीन से तुल्य स्तरों तक कृषि से अपना रोज़गार जीडीपी अंश घटाने में सफल रहा है।

बोध प्रश्न 2

1) विकास में अभावों का अर्थ है – संवृद्धि के साथ बढ़ती प्रति व्यक्ति आय के बावजूद गरीबी और बेरोज़गारी की व्यापकता। यह समाज में बढ़ती असमानता को भी इंगित करता है।

2) भारत, श्रीलंका और चीन के उदाहरण में देखा जा सकता है कि बढ़ती आय (जीडीपी) के साथ गरीबी घटी है। बहरहाल, दक्षिण-अफ्रीका के मामले में, आय तो बढ़ी है मगर निर्धनता अनुपात भी बहुत ऊपर चला गया है (वर्ष 2014 में 56 प्रतिशत)।

3) ऐसा इसलिए है कि यहाँ रोज़गार का बड़ा भाग अनौपचारिक है, जहाँ प्रच्छन्न बेरोज़गारी बहुत अधिक होती है।

4) विभिन्न देशों के बीच तुल्य आय विषयक आँकड़े तैयार करने के लिए विश्व असमानता डेटाबेस (WID) द्वारा अनूठी विधियाँ अपनाई गई हैं। इसके रुझान दर्शाते हैं कि दक्षिण-एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में असमानता भारत और बांग्लादेश द्वारा 40^{+} प्रतिशत जबकि नेपाल और पाकिस्तान द्वारा 30 प्रतिशत से किंचित् ही ऊपर रहकर दर्शाई जाती है। श्रीलंका और चीन में यह उच्चतम (दोनों 49 प्रतिशत के बराबर) है।

5) विकसित देश भी उच्च असमानता दर्शाते हैं, यथा– इंग्लैंड 32 प्रतिशत और अमेरिका 39 प्रतिशत (वर्ष 2018 में)। यह इसी वर्ष (2018 में) नेपाल 33 प्रतिशत और पाकिस्तान 32 प्रतिशत से तुल्य है।

बोध प्रश्न 3

1) ऐसा इसलिए है कि इससे अपेक्षित था कि यह लोगों की शैक्षिक प्रस्थिति में ऐतिहासिक उपेक्षा अथवा उपलब्धि को उजागर करेगा। अब हाल ही में ज़ोर शिक्षा की 'सुलभता, निष्पक्षता एवं गुणवत्ता' पर दिया जाने लगा है।

2) उसे 25 प्रतिशत से भी अधिक पात्र छात्र माध्यमिक-शिक्षा प्रणाली से बाहर दर्शाने वाले बांग्लादेश और नेपाल की श्रेणी में रखा जाता है।

3) भारत 6.5 वर्ष पर तय स्कूली शिक्षा के अपने मध्य वर्षों के साथ तुल्य माने गए 10 देशों के लगभग बीच में दर्शाया जाता है। तृतीयक शिक्षा में नामांकन के लिहाज से, भारत की स्थिति दक्षिण अफ्रीका समेत दक्षिण एशिया के अन्य चार देशों से बेहतर है।

4) i) कुल स्वास्थ्य व्यय की प्रतिशतता स्वरूप राजकीय व्यय, तथा

ii) जीडीपी की प्रतिशतता में व्यक्त स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च।

5) सामाजिक प्रगति को इन शब्दों में परिभाषित किया जाता है – अपने नागरिकों की मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी समाज की क्षमता। सामाजिक प्रगति सूचकांक (SPI) के जिहाज से, भारत, बांग्लादेश, नेपाल व पाकिस्तान से बस थोड़ा ही ऊपर दिखाई पड़ता है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY